

ADCs द्वारा 125वें संवधान संशोधन वधियक को पारति करने की मांग

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मोजोरम और त्रिपुरा के 10 स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs) के मुख्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Chief Executive Magistrates- CEMs) ने केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की और [125वें संवधान संशोधन वधियक](#) को पारति करने की मांग रखी।

- इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने वधियक से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का नरिणय लयिा।

125वें संवधान संशोधन वधियक में प्रस्तावति संशोधन क्या हैं?

- वधियक का उद्देश्य संवधान की [छठी अनुसूची](#) के तहत जनजातीय स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करना है।
- ग्राम एवं नगर परिषदें:
 - प्रस्ताव में मौजूदा ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के साथ-साथ ग्राम एवं नगर परिषदों का गठन भी शामिल है।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग गाँवों या गाँवों के समूहों के लिये [ग्राम परिषदें \(Village Councils\)](#) स्थापति की जाएंगी, जबकि प्रत्येक ज़िले के शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदें स्थापति की जाएंगी।
- ज़िला परिषदों को नमिनलखिति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा:
 - ग्राम और नगर परिषदों की संख्या एवं संरचना।
 - इन परिषदों में चुनाव हेतु नरिवाचन क्षेत्रों का परसीमन।
 - ग्राम एवं नगर परिषदों की शक्तियाँ और कार्य।
- शक्तियों के हस्तांतरण के नयिम: [राज्यपाल](#) को ग्राम एवं नगर परिषदों को शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण हेतु नयिम बनाने का अधिकार होगा।
 - इन नयिमों में नमिनलखिति शामिल हो सकते हैं:
 - आर्थिक विकास योजनाओं की तैयारी।
 - भूमिसुधारों का कारयानवयन।
 - शहरी एवं नगरीय नयिोजन।
 - अन्य उत्तरदायित्वों के साथ-साथ भूमिउपयोग का वनियमन।
 - वधियक में प्रस्ताव कयिा गया है कि राज्यपाल दल-बदल/दल -परवित्तन (Defection) के आधार पर परिषद सदस्यों की अनर्रहता संबंधी नयिम भी बना सकता है।
- राज्य वित्त आयोग: वधियक में ज़िला, ग्राम और नगर परिषदों की वित्तीय स्थितिका आकलन करने के लिये इन राज्यों में एक [वित्त आयोग](#) की नयिुक्ता प्रावधान है। आयोग नमिनलखिति के संबंध में सफिररशें करेगा:
 - राज्य और ज़िला परिषदों के बीच करों का वितरण।
 - राज्य की [संचति नधि](#) से ज़िला, ग्राम और नगर परिषदों को अनुदान सहायता।
- परिषदों के चुनाव: ज़िला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, ग्राम परिषदों और नगर परिषदों के चुनावों की देख-रेख [राज्य नरिवाचन आयोग](#) द्वारा की जाएगी, जसिकी नयिुक्ता इन चार राज्यों के लिये राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- वधियक की वर्तमान स्थिति:
 - संवधान (125वाँ संशोधन) वधियक 2019, को राज्यसभा में प्रस्तुत कयिा गया था और बाद में इसे गृह मामलों पर वभिाग-संबंधति संसदीय स्थायी समिति को भेज दयिा गया।
 - समिति ने वर्ष 2020 में प्रस्तुत अपनी रपिर्ट में वधियक के बारे में कई चतिाएँ वयक्त थीं और तब से यह लंबति है।

संवधान की छठी अनुसूची क्या है?

- **क्षेत्र:** इस अनुसूची के तहत जनजातीय अधिकारों के संरक्षण हेतु असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है।
- **संवैधानिक आधार:** इस अनुसूची के तहत [अनुच्छेद 244 \(2\)](#) (छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे) और [अनुच्छेद 275 \(1\)](#) (यह भारत की समेकित नधिसे अनुदान सहायता को सुनिश्चित करता है) आते हैं।
- **स्वायत्तता:** इस अनुसूची के तहत स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADCs) में शासन का प्रावधान किया गया है, जिसमें भूमि, वन, कृषि, वरिसत, सीमा शुल्क और करों पर कानून का निर्माण करना शामिल है।
- **शासन:** ADC वधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के साथ छोटे राज्यों की तरह कार्य करते हैं।

स्वायत्त ज़िला परिषदें (ADCs) क्या हैं?

- **परिचय:** ADCs संवधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244) के तहत पूर्वोत्तर भारत में बनाए गए संवधानिक साधन हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।
 - **राज्यपाल का प्राधिकार:** स्वायत्त ज़िलों को उनके क्षेत्रों और सीमाओं सहित व्यवस्थित, पुनर्गठित एवं संशोधित कर सकता है।
 - **जनजातीय वितरण:** यदि कोई जनजातियाँ मौजूद हैं, तो राज्यपाल ज़िले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र का गठन कर सकता है।
- **संरचना:**
 - **ज़िला परिषद:** प्रत्येक ज़िले में 30 सदस्यों की एक परिषद होती है (4 राज्यपाल द्वारा नामित, 26 निर्वाचित), जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
 - **क्षेत्रीय/आंचलिक परिषद:** प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की अपनी परिषद होती है।
 - **प्रशासन:** ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने क्षेत्राधिकार का प्रबंधन करती हैं तथा जनजातीय विवादों के लिये ग्राम परिषदें या न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं। अपील की सुनवाई राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाती है।
- वर्तमान में 10 स्वायत्त परिषदें अस्तित्व में हैं - असम, मेघालय और मज़ोरम में तीन-तीन तथा त्रिपुरा में एक।



પ્રથમ અનુસૂચી

- ## द्वितीय अनुसूची

- ## तृतीय अनुसूची

- ## चौथी अनुसूची

- ## पाँचवीं अनुसूची

- अनुच्छेद: 244
- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण

છઠી અનુસૂચી

- ## सातवीं अनुसूची

- ## આઠવીં અનુસૂચી

- ## नौवीं अनुसूची (पहला संशोधन अधिनियम, 1951)

- दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985)**

- ગ્યારહવીં અનુસૂચી (73વાં સંશોધન અધિનિયમ, 1992)**

- बारहवीं अनुसूची (74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992)**

- अनुच्छेद: 243-W
- नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????:

(a) तीसरी अनुसूची
(b) पाँचवी अनुसूची
(c) नौवी अनुसूची
(d) बारहवी अनुसूची

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/adcs-raise-demand-to-pass-125th-constitutional-amendment-bill>

